मंगलवार, 23 जून, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

डेरिल कलिनन ने वैभव सूर्यवंशी के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

करिश्मा कपूर ने पूरे किए बॉलीवुड में 35 साल

Page-05

ऋतब्रत बनर्जी वाले गुट ने की अभिषेक बनर्जी को सस्पेंड करने की घोषणा

तृणमूल कांग्रेस (TMC) में अंदरूनी कलह का एक और संकेत तब मिला, जब बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले एक गुट ने सोमवार को एक नई कमेटी बनाने और पार्टी में दूसरे सबसे बड़े नेता अभिषेक बनर्जी को सस्पेंड करने की घोषणा की। जानकारी के मुताबिक टीएमसी के बागी विधायकों ने तृणमूल कांग्रेस के पार्षदों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में तृणमूल कांग्रेस के नाम और लोगो का इस्तेमाल किया गया, लेकिन ममता बनर्जी की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं किया गया। साथ ही, सूत्रों के मुताबिक, इस सीक्रेट मीटिंग से आने वाले दिनों में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला किया गया है। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के विपक्षी नेता और बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी ने आज दोपहर न्यू टाउन के एक होटल में तृणमूल के पुराने और मौजूदा पार्षदों के एक ग्रुप से एक जरूरी सीक्रेट मीटिंग की। इस सीक्रेट मीटिंग में करीब 60 से 70 पार्षद और बड़े नेता शामिल हुए। इस मीटिंग में राज्य के पुराने मंत्री और विधायक जावेद खान, अरूप रॉय और कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कई पार्षद मौजूद थे। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में 11 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। अरूप रॉय को इस नेशनल वर्किंग कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया गया है। सूत्रों का यह भी कहना है कि एक प्रस्ताव पास करके अभिषेक बनर्जी को सस्पेंड कर दिया गया है। गौरतलब है कि इस सीक्रेट मीटिंग में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नाम और लोगो का इस्तेमाल तो किया गया, लेकिन ममता बनर्जी की कोई तस्वीर इस्तेमाल नहीं की गई।

लखनऊ के कोचिंग सेंटर में भीषण आग

मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में स्थित एक कोचिंग सेंटर में सोमवार को भीषण आग लग गई। इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक, ये कोचिंग दुकान के ऊपर चल रही थी। जब आग लगी तो कई छात्रों ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान बचाई। कोचिंग सेंटर में आग लगने की खबर मिलते ही प्रशासन और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम किया। मौके पर अब भी राहत और बचाव का काम जारी है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीमें तत्काल मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने स्थानीय लोगों की सहायता से बचाव अभियान शुरू किया और कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। आग की लपटें तेजी से फैलने के कारण बचाव कार्य में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आसपास की इमारतों को भी एहतियातन खाली कराया गया।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं।प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का संभावित कारण माना जा रहा है, हालांकि अधिकारी अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रहे हैं। फोरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया है, जो तकनीकी पहलुओं की जांच करेगी।स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि इमारत में अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। यदि समय रहते दमकल विभाग मौके पर नहीं पहुंचता तो बड़ा हादसा हो सकता था। प्रशासन ने कहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।इस घटना ने एक बार फिर व्यावसायिक और शैक्षणिक संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे संस्थानों में नियमित सुरक्षा ऑडिट और आपातकालीन निकासी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके। लखनऊ अग्निकांड पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने मृतकों के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। साथ ही पीएम ने मृतकों के परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है...पीएम मोदी ने मृतकों के परिवार के लिए 2-2 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के C M योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हुई घटना की रिपोर्ट तलब की है। सीएम योगी ने राज्य के DGP और अपर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है और घटना की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है।

राम मंदिर विवाद: केजरीवाल ने निष्पक्ष जांच की मांग की

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्र किए गए चंदे को लेकर देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर निर्माण से जुड़े वित्तीय लेन-देन में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। केजरीवाल ने कहा कि देशभर के करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ मंदिर निर्माण के लिए योगदान दिया है, इसलिए चंदे से जुड़े सभी पहलुओं में पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए।प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने दावा किया कि उन्हें मंदिर निर्माण से जुड़े वित्तीय प्रबंधन को लेकर कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकार की अनियमितता हुई है तो उसकी स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वह आगामी दिनों में अयोध्या का दौरा कर स्थानीय लोगों और संबंधित पक्षों से मुलाकात करेंगे।दूसरी ओर, राम मंदिर ट्रस्ट और भाजपा ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों का कहना है कि मंदिर निर्माण से संबंधित सभी वित्तीय लेन-देन निर्धारित नियमों और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किए जा रहे हैं। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष धार्मिक आस्था से जुड़े विषयों को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहा है।

पश्चिम बंगाल बजट: सरकारी कर्मचारियों को 20% डीए

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार ने सोमवार को अपना पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए सरकारी कर्मचारियों, युवाओं और महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं। बजट की सबसे प्रमुख घोषणा राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए 20 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की रही। लंबे समय से डीए वृद्धि की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए यह फैसला बड़ी राहत माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए 'युवा शक्ति योजना' शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, स्टार्टअप और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विशेष वित्तीय सहायता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि आने वाले वर्षों में राज्य में नए औद्योगिक निवेश को आकर्षित कर रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जाएगी।बजट में महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने, स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने तथा सुरक्षा संबंधी योजनाओं के लिए अलग फंड आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिए भी बजट में पर्याप्त राशि निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री और राज्य सरकार ने बजट को विकास और जनकल्याण आधारित बताया है। वहीं, विपक्ष ने बजट के वित्तीय प्रबंधन और घोषणाओं की व्यवहारिकता पर सवाल उठाए हैं। हालांकि भाजपा नेताओं का कहना है कि यह बजट राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने बजट का समर्थन करते हुए कहा कि यह पश्चिम बंगाल को आर्थिक चुनौतियों से बाहर निकालने और उसके औद्योगिक तथा सांस्कृतिक गौरव को पुनर्स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बजट का असर आने वाले वर्षों में राज्य की राजनीति और विकास की दिशा पर दिखाई देगा।

रूसी सीमा के भीतर यूक्रेनी हमलों से बढ़ा तनाव

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध एक नए और खतरनाक चरण में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है। ताजा घटनाक्रम में यूक्रेनी सेना ने रूसी सीमा के भीतर कई इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और अधिक बढ़ गया है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन की यह रणनीति युद्ध की दिशा बदल सकती है।रिपोर्टों के अनुसार, यूक्रेनी बलों ने सीमावर्ती रूसी क्षेत्रों में सैन्य प्रतिष्ठानों और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया है। इसके जवाब में रूस ने भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए सीमावर्ती इलाकों में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी है। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय ने स्थिति की समीक्षा के लिए आपात बैठक बुलाई और संबंधित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं।विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन की यह कार्रवाई केवल सैन्य दबाव बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य रूस की रणनीतिक क्षमताओं को चुनौती देना भी हो सकता है। दूसरी ओर, रूस ने इन हमलों को गंभीर उकसावे की कार्रवाई बताते हुए जवाबी कदम उठाने की चेतावनी दी है। युद्ध के इस नए चरण ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं को भी बढ़ा दिया है।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर का इस्तीफा, लेबर पार्टी में नेतृत्व संकट गहराया

यूनाइटेड किंगडम की राजनीति में उस समय बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर राष्ट्र को संबोधित करते हुए स्टार्मर ने अपने कार्यकाल को समाप्त करने का ऐलान किया। उनके इस फैसले के बाद ब्रिटेन में राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल बन गया है और लेबर पार्टी के भीतर नए नेतृत्व की तलाश तेज हो गई है।अपने भावुक संबोधन में स्टार्मर ने कहा कि दो वर्ष पहले प्रधानमंत्री पद संभालना उनके जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण था। उन्होंने कहा कि राजनीति में आने का उनका उद्देश्य आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना था। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, निवेश

बढ़ा और कामगारों के अधिकारों को सशक्त बनाया गया।स्टार्मर ने दावा किया कि उनकी सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) की प्रतीक्षा सूची को कम करने, मजदूरी दर बढ़ाने और रक्षा खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि करने जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की नीतियों के कारण हजारों परिवारों को राहत मिली और गरीबी उन्मूलन की दिशा में प्रगति हुई।हालांकि, उनके कार्यकाल के दौरान कई नीतिगत फैसलों को लेकर विवाद भी सामने आए। विपक्ष और लेबर पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष के कारण पिछले कुछ महीनों से स्टार्मर पर लगातार दबाव बढ़ रहा था। आलोचकों का आरोप था कि सरकार चुनावी वादों के अनुरूप लोगों के जीवन स्तर में अपेक्षित सुधार नहीं ला सकी।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने दिया इस्तीफा

पार्टी में बढ़ते विरोध के बीच छोड़ा पद

2024 के आम चुनाव में लेबर पार्टी की ज़बरदस्त जीत पर बात करते हुए, स्टार्मर ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने आर्थिक विकास, बढ़ती मज़दूरी, ज़्यादा निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, NHS की वेटिंग लिस्ट में कमी, कामगारों और किराएदारों के बेहतर अधिकार, रक्षा पर ज़्यादा खर्च, छोटी नावों से होने वाली आवाजाही में कमी और बच्चों की ग़रीबी से निपटने की कोशिशों का ज़िक्र किया।

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने अपनी ही पार्टी के भीतर से बढ़ते अंदरूनी दबाव के बीच डाउनिंग स्ट्रीट में अपने कार्यकाल को समाप्त करते हुए, प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता के पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी है। स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट से बाहर आए जहाँ उनका स्वागत लोगों की नारेबाजी और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ किया गया, जिसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा बयान पढ़ा और इस दौरान उन्होंने दो साल पहले डाउनिंग स्ट्रीट में अपने आगमन को जीवन का "सबसे गर्व का पल" बताते हुए याद किया और कहा कि उन्होंने राजनीति में कदम ही करोड़ों लोगों के जीवन को बदलने के उद्देश्य से रखा था। 2024 के आम चुनाव में लेबर पार्टी की ज़बरदस्त जीत पर बात करते हुए, स्टार्मर ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने आर्थिक विकास, बढ़ती मज़दूरी, ज़्यादा निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, NHS की वेटिंग लिस्ट में कमी, कामगारों और किराएदारों के बेहतर अधिकार, रक्षा पर ज़्यादा खर्च, छोटी नावों से होने वाली आवाजाही में कमी और बच्चों की ग़रीबी से निपटने की कोशिशों का ज़िक्र किया। स्टारमर ने अपनी सरकार के कामकाज का ब्योरा देते हुए कहा कि मैंने जो भी फ़ैसला लिया है, उसमें हमेशा उस देश को प्राथमिकता दी है जिससे मैं प्यार करता हूँ। हमारी अर्थव्यवस्था मज़बूत हुई है और हम अपने साथियों की तुलना में तेज़ी से आगे बढ रहे हैं। जब से हम सत्ता में आए हैं, हर महीने महंगाई की तुलना में वेतन तेज़ी से बढ़ा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार ने एक पीढ़ी में कामगारों और किराएदारों के अधिकारों में सबसे बड़ा सुधार किया है, कोल्ड वॉर के बाद से रक्षा खर्च में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की है, और नीतिगत फैसलों के ज़रिए पाँच लाख बच्चों को गरीबी से बाहर निकाला है। हालांकि, कई विवादों, नीतियों में बदलाव और लोगों का समर्थन घटने की वजह से स्टारमर पर महीनों से लगातार दबाव बना हुआ था। लेबर पार्टी के अंदर और बाहर के आलोचकों ने उनकी सरकार पर आरोप लगाया कि वह 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादों के मुताबिक लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में नाकाम रही। यह दबाव तब और बढ़ गया जब लेबर पार्टी के ही प्रतिद्वंद्वी एंडी बर्नहम ने संसदीय सीट जीती, जिससे उन्हें औपचारिक रूप से नेतृत्व को चुनौती देने का मौका मिल गया। लेबर पार्टी के 100 से ज़्यादा सांसदों जो हाउस ऑफ़ कॉमन्स में पार्टी के प्रतिनिधियों का लगभग एक-चौथाई हिस्सा हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्टारमर से इस्तीफ़ा देने या पद छोड़ने के लिए एक स्पष्ट समय-सीमा तय करने की मांग की थी।

अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत एक नाटकीय मोड़ पर

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच अहम बातचीत का पहला दौर रविवार को एक नाटकीय मोड़ पर पहुँच गया, जब ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने तेहरान के खिलाफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया धमकी पर आपत्ति जताते हुए कुछ देर के लिए बैठक स्थल छोड़ दिया। इससे पाकिस्तानी और अमेरिकी अधिकारियों के सामने एक अजीब राजनयिक स्थिति पैदा हो गई। बर्गेनस्टॉक रिज़ॉर्ट, जहाँ बातचीत हो रही थी। वहां का एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो गया। इस वीडियो में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ से थोड़ी देर बात करते हुए और फिर मुड़कर ईरानी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ कमरे से बाहर जाते हुए देखा गया। अचानक चले जाने से शरीफ़ साफ़ तौर पर हैरान दिखे और बाद में उन्हें पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर की ओर इशारा करते हुए देखा गया। कुछ ही फ़ीट दूर खड़े अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यह नज़ारा देखा और फिर पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के पास गए। यह घटना हाल ही में हुए इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MoU) के तहत बातचीत के शुरुआती दौर में हुई। इस MoU का मकसद इलाके में हफ़्तों से चल रहे सैन्य तनाव को कम करने के लिए ईरान, अमेरिका, पाकिस्तान और कतर को एक साथ लाना था। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक, औपचारिक बातचीत शुरू होने से पहले ही तनाव पैदा हो गया। तेहरान ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ पहले से तय संयुक्त फ़ोटो सेशन में शामिल होने से इनकार कर दिया और इसे अमेरिका का "मीडिया शो" करार दिया।

कावेरी विवाद: मेकेदातु परियोजना का हर स्तर पर विरोध करेगा तमिलनाडु

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

मंत्री एन. आनंद ने सोमवार को कहा कि कर्नाटक के प्रस्तावित मेकेदातु बांध प्रोजेक्ट के मामले में तमिलनाडु सरकार कावेरी नदी के पानी पर राज्य के अधिकारों या किसानों की आजीविका से कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की सुरक्षा और तमिलनाडु के ऐतिहासिक जल अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ग्रामीण विकास और जल संसाधन विभाग संभालने वाले आनंद ने कहा कि कर्नाटक द्वारा बैलेंसिंग रिज़र्वोयर प्रोजेक्ट के लिए फिर से कोशिशें शुरू करने के बाद सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें कानूनी विशेषज्ञों से सलाह-मशविरा, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में मामला ले जाना शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और इस प्रोजेक्ट के प्रति राज्य के विरोध से उन्हें अवगत कराया था। मंत्री ने कहा कि विपक्ष की पार्टी DMK की ट्रिब्यूनल बनाने की मांग को मानते हुए, विधानसभा ने 19 जून को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया था। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल बनाना एक रणनीतिक कदम था ताकि यह पक्का किया जा सके कि कर्नाटक और केंद्र सरकार मेकेदातु बांध प्रोजेक्ट पर एकतरफा तरीके से आगे न बढ़ सकें। आनंद ने यह भी कहा कि सरकार का रुख यह है कि 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले ने कावेरी के पानी में तमिलनाडु का हिस्सा सुरक्षित कर दिया है और कोई भी नया ट्रिब्यूनल इसे बदल नहीं सकता। उन्होंने साफ़ किया कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को खारिज नहीं किया है, बल्कि उसे बिना किसी टिप्पणी के केंद्रीय जल आयोग को वापस भेज दिया है, जिसका मतलब है कि जोखिम अभी भी बना हुआ है। डीएमके के पूर्व मंत्री ईवी वेलु ने कहा कि उनकी पार्टी ने इस मुद्दे पर नई सरकार के साथ सहयोग करने का फ़ैसला किया है और विपक्ष के नेता ने राज्य की कानूनी स्थिति को मज़बूत करने के लिए एक ज़रूरी संशोधन पेश किया है।

शहबाज शरीफ ने कतर और पाकिस्तान की टीम को दिया श्रेय

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच हुई अहम बातचीत को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि बैठक अच्छे माहौल में हुई और कई मुद्दों पर सकारात्मक प्रगति हुई है। पाक पीएम के मुताबिक, दोनों देश अगले 60 दिनों के भीतर एक अंतिम समझौते तक पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमत हुए हैं। इसके लिए एक रोडमैप तैयार किया गया है। साथ ही बातचीत की निगरानी के लिए एक उच्चस्तरीय समिति बनाई जाएगी और आगे भी तकनीकी स्तर पर चर्चा जारी रहेगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान शांति और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिशों में आगे भी अपनी भूमिका निभाता रहेगा। शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान की बातचीत की सफलता का श्रेय कतर और पाकिस्तान की टीम को दिया है। शरीफ ने कहा कि कतर ने ऐसा माहौल बनाने में मदद की जिससे अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत आगे बढ़ने में सफल रही है। साथ ही पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर के प्रयासों को भी सराहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वार्ता को सफल बनाने के लिए असीम मुनीर ने लगातार मेहनत की है उनके प्रयासों के बिना यह संभव नहीं था। उप प्रधानमंत्री इशाक डार, गृह मंत्री मोहसिन नकवी और विदेश मंत्रालय की टीम का भी आभार जताया है। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से कई मुद्दों को लेकर आपसी मतभेद बने हुए हैं। जिसमें ईरान का परमाणु कार्यक्रम, उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध, विदेशों में फ्रीज हुई ईरानी संपत्तियां और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले शामिल हैं। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए स्विट्ज़रलैंड में यह बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में दोनों पक्षों के बीच प्रगति की बात कही जा रही है लेकिन अभी कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है। फिलहाल एक रोडमैप तैयार किया गया है जिसके तहत अगले 60 दिनों में आगे की बातचीत होगी। इस दौरान तकनीकी स्तर पर कई दौर की चर्चा होने की संभावना है।

अमेरिका ने भारत के साथ एक डिफेंस डील को हरी झंडी दे दी

भारत की मारक क्षमता को सुपर चार्ज कर देगी

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

अमेरिका ने भारत के साथ एक ऐसी डिफेंस डील को हरी झंडी दे दी है। मंजूरी दे दी है जो सीधे तौर पर हिमालय की चोटियों पर भारत की मारक क्षमता को सुपर चार्ज कर देगी। 482.2 मिलियन डॉलर यानी करीब 4000 करोड़ का यह महा पैकेज। यह कोई साधारण खरीद फरोख्त नहीं है। बल्कि यह भारत के दो सबसे घातक हथियारों अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और M7 अल्ट्रा लाइट होज़र की उम्र और ताकत बढ़ाने का एक ब्रह्मास्त्र है। दरअसल इस पूरी डील को समझने के लिए हमें अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन के उन दस्तावेजों को देखना होगा जो हाल ही में सार्वजनिक हुए डीएससीए यानी कि यूएस डिफेंस सिक्योरिटी कॉरपोरेशन एजेंसी ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की। इस 482.2 मिलियन डॉलर के निवेश को दो मुख्य स्तंभों पर खड़ा किया गया। पहला स्तंभ है M7 होइजर का सस्टेनमेंट पैकेज $30 मिलियन का। यह हिस्सा भारतीय सेना के लिए है। इनमें तोपों के स्पेयर पार्ट्स, रखरखाव, ट्रेनिंग और सबसे महत्वपूर्ण डेपो कैपेबिलिटी शामिल है। यानी भारत के पास अब इन तोपों को स्वदेशी स्तर पर लंबे समय तक मेंटेन करने की क्षमता होगी। AH64E Apacचे का सपोर्ट पैकेज जो 198.2 मिलियन का है। यह हिस्सा भारतीय वायुसेना और थल सेना के बेड़े में शामिल अपाचे हेलीकॉप्टर्स के लिए है। इसमें लॉजिस्टिक, टेक्निकल डाटा, पब्लिकेशन और ट्रेनिंग शामिल है। यहां एक बात गौर करने वाली यह है कि अक्सर हम नए हथियार खरीद की बात करते हैं। लेकिन उनकी लाइफ साइकिल को बनाए रखना उससे भी बड़ी चुनौती होती है। अमेरिका से मिलने वाला यह सस्टेन मिंट सपोर्ट यह सुनिश्चित करता है कि अगर कल युद्ध छिड़ता है तो भारत के पास भारत के स्पेयर पार्ट्स की कमी नहीं होगी और यह वॉर वेस्टेड रिजर्व को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब बात करते हैं उस हथियार की जिसने लद्दाख और अरुणाचल में चीन की सेना की नींद उड़ा रखी है। उसका नाम है M7 अल्ट्रा लाइट होइज़र। भारत ने करीब 145 ऐसी तोपें खरीदे थी। अब यह क्यों है इतनी खास? यह जान लीजिए। दरअसल M7 दुनिया की इकलौती ऐसी तोप है जो 155 एमएम की होने के बावजूद इतनी हल्की है कि इसे पहाड़ों की उन चोटियों पर भी तैनात किया जा सकता है जहां सड़कें तक नहीं बनती है। यह टाइटेनियम ऑयल से बनी हुई है।

संपादक की कलम से

महंगाई और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच संतुलन की चुनौती:

भारत इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां आर्थिक विकास की संभावनाएं और वैश्विक चुनौतियां एक साथ मौजूद हैं। एक ओर देश दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, वहीं दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती अनिश्चितताएं सरकार और नीति निर्माताओं के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, वैश्विक व्यापार की अनिश्चितता और मानसून को लेकर आशंकाएं ऐसे कारक हैं जो आने वाले महीनों में देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं।हाल ही में वित्त मंत्री द्वारा व्यक्त की गई चिंताएं इस बात का संकेत हैं कि सरकार स्थिति की गंभीरता को समझ रही है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए महंगाई केवल आर्थिक विषय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब खाद्य पदार्थों, ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका सबसे अधिक असर निम्न और मध्यम वर्ग पर पड़ता है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी केवल आर्थिक आंकड़ों को बेहतर बनाए रखने तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि आम नागरिक के जीवन को भी सहज बनाए रखना आवश्यक हो जाता है।देश की कृषि व्यवस्था अब भी मानसून पर काफी हद तक निर्भर है। यदि वर्षा सामान्य से कम रहती है तो खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित हो सकता है, जिसका सीधा असर बाजार कीमतों पर दिखाई देगा। सरकार को अभी से भंडारण, आपूर्ति और वितरण व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए ताकि किसी भी संभावित संकट से समय रहते निपटा जा सके। साथ ही किसानों को तकनीकी सहायता, सिंचाई सुविधाएं और पर्याप्त समर्थन मूल्य उपलब्ध कराना भी जरूरी है।दूसरी ओर, वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता भारत के लिए विशेष चिंता का विषय है। देश अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात करता है। तेल की कीमतों में वृद्धि केवल पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं रहती, बल्कि परिवहन, उद्योग और कृषि क्षेत्र के माध्यम से पूरे अर्थतंत्र को प्रभावित करती है। इसलिए ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।विपक्ष द्वारा महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाना लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है। हालांकि इन विषयों पर केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से समाधान नहीं निकलेगा। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार और विपक्ष दोनों राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर रचनात्मक संवाद करें। संसद का आगामी सत्र इस दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है।भारत ने अतीत में कई आर्थिक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। आज भी देश के पास मजबूत संस्थागत ढांचा, विशाल घरेलू बाजार और युवा जनसंख्या जैसी बड़ी ताकतें मौजूद हैं। आवश्यकता केवल दूरदर्शी नीति, प्रभावी क्रियान्वयन और राजनीतिक इच्छाशक्ति की है। यदि सरकार समय रहते आवश्यक कदम उठाती है और सभी हितधारकों को साथ लेकर चलती है, तो वर्तमान चुनौतियां भी देश की प्रगति को रोक नहीं पाएंगी। बल्कि यही चुनौतियां भारत को अधिक आत्मनिर्भर, मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का अवसर भी बन सकती हैं।

विधान परिषद चुनाव में शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार नरेंद्र दराडे की हार के बाद सियासी घमासान तेज

भले ही महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में महायुति ने 17 में से 16 सीटों पर जीत दर्ज की है, लेकिन नासिक का परिणाम गठबंधन के लिए चिंता का विषय बन गया है। भाजपा के बागी उम्मीदवार की जीत और शिवसेना उम्मीदवार की हार ने स्थानीय स्तर पर राजनीतिक समीकरणों और अंदरूनी नाराजगी को उजागर किया है।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव (MLC Election) में नासिक सीट पर शिवसेना (शिंदे गुट) के आधिकारिक उम्मीदवार नरेंद्र दराडे की हार के बाद महायुति में सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा के बागी उम्मीदवार और निर्दलीय प्रत्याशी गोकुल गीते ने नरेंद्र दराडे को 109 वोटों के अंतर से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया। अब इस हार को लेकर महायुति के भीतर ही सवाल उठने लगे हैं। भाजपा, शिवसेना (शिंदे गुट) और सुनेत्रा पवार नीत एनसीपी महायुति के सहयोगी दल हैं। हार के बाद नरेंद्र दराडे ने दावा किया कि महायुति के तीन नेताओं ने उनके साथ विश्वासघात किया है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। सियासी हलकों में चर्चा है कि दराडे अपनी हार के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री गिरीश महाजन को जिम्मेदार मानते है। हालांकि, शिवसेना नेता और मंत्री उदय सामंत ने अपने उम्मीदवार की हार के कारणों का पता लगाने के लिए गहन समीक्षा करने की बात कही है। नासिक निर्वाचन क्षेत्र में गोकुल गीते भाजपा के बागी उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे थे और उन्होंने महायुति के आधिकारिक उम्मीदवार नरेंद्र दराडे को हराकर सभी को चौंका दिया। इस सीट पर उस समय विवाद खड़ा हो गया जब भाजपा नेता गोकुल गीते ने दराडे के खिलाफ अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। उन्होंने आरोप लगाया कि दराडे ने उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप के बाद गीते ने अपना चुनाव प्रचार स्थगित कर दिया था, लेकिन नाम वापसी की अंतिम तारीख गुजर जाने के कारण उनका नाम मतपत्र पर बना रहा। भले ही गीते ने अपना व्यक्तिगत प्रचार रोक दिया था, लेकिन उनके समर्थक लगातार उनके पक्ष में प्रचार और जनसंपर्क अभियान चलाते रहे। नासिक चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता उदय सामंत ने कहा कि पार्टी इस हार के पीछे के कारणों की विस्तृत समीक्षा करेगी। उन्होंने कहा, "गोकुल गीते नासिक से विजयी हुए हैं और हमारी शिवसेना के उम्मीदवार नरेंद्र दराडे को हार का सामना करना पड़ा है। यह पराजय किन कारणों से हुई और इसमें कौन-कौन शामिल था, इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार कर पार्टी प्रमुख और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सौंपी जाएगी।" सामंत ने कहा कि पार्टी के पास जितने वोट आने की उम्मीद थी, उतने वोट नहीं मिले। आखिर वोटों की कमी क्यों हुई, इसका गहन विश्लेषण किया जाएगा। नासिक विधान परिषद चुनाव के दौरान भाजपा के बागी उम्मीदवार गोकुल गीते को मैदान से हटाने के लिए आखिरी समय तक प्रयास किए गए थे। बताया जा रहा है कि भाजपा नेता गिरीश महाजन और शिवसेना के उदय सामंत ने व्यक्तिगत रूप से गीते को मनाने की कोशिश की थी।

अब "ऑपरेशन टाइगर" पूरी तरह सफल: शिंदे

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने कहा, "आज हमारे साथ 6 सांसद शामिल हुए हैं। संजय हरिभाऊ जाधव, भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे, ओमप्रकाश भूपालसिंह निंबालकर, संजय दीना पाटिल, संजय उत्तमराव देशमुख और नागेश बापुराव पाटिल अष्टिकर। तो हमारे साथ यहां 3 संजय हैं। हमारे यहां एक और संजय राठौड़ (विधायक) भी हैं। जब हमारे यहां संजय हैं, तो किसी और संजय के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, और आप जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं।" एकनाथ शिंदे ने ये भी कहा कि अब एक नहीं छह टाइगर यहां मौजूद हैं। शिंदे ने कहा कि हम कोई ऑपरेशन आधा अधूरा नहीं करते। ऑपरेशन पूरा हो चुका है। सभी प्रक्रिया का पालन कर छह सांसद हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने रविवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उनकी पार्टी लगातार मजबूत हो रही है और अब "ऑपरेशन टाइगर" पूरी तरह सफल हो चुका है। शिंदे ने कहा कि पार्टी के वर्धापन दिवस पर उन्होंने नए नेताओं के शामिल होने के संकेत दिए थे और अब छह सांसद उनकी शिवसेना के साथ आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनके परिवार में "कट्टर शिवसैनिकों" का स्वागत किया गया है।उन्होंने 2022 में हुए राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा, "चार साल पहले जब हमने उठाव किया था, तब 40 विधायक हमारे साथ थे। उस समय हमारा उद्देश्य शिवसेना और बालासाहेब ठाकरे के विचारों को बचाना था। अब दूसरा अध्याय शुरू हो चुका है और छह सांसद हमारे साथ जुड़े हैं।" शिंदे ने कहा कि पार्टी में शामिल हुए सभी नेता जमीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ता हैं और वे किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र और लोगों के विकास के लिए शिवसेना के साथ आए हैं। उन्होंने कहा, "हम किसी के रास्ते में नहीं आते, लेकिन अगर कोई हमारे रास्ते में आता है तो हम उसे छोड़ते भी नहीं।" उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जनता ने उनकी नीयत और विचारधारा पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि विधायक, सांसद, सरपंच और पार्षद जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं और यह जनसमर्थन उनकी साफ नीयत और विकास के एजेंडे का परिणाम है। शिंदे ने कहा, "विचारधारा महत्वपूर्ण होती है और लोगों ने हमारी विचारधारा को स्वीकार किया है। हमारा एजेंडा विकास और लोगों की मदद करना है।"

उत्तर प्रदेश में हैट्रिक बनाने के लिए तैयारियां तेज हो गई,जल्द ही नई प्रदेश टीम की घोषणा करेगी

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल में भारी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जहां पंजाब के चुनाव अभियान की शुरुआत शनिवार से कर दी है वहीं उत्तर प्रदेश में हैट्रिक बनाने के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। पार्टी वहां जल्द ही नई प्रदेश टीम की घोषणा करेगी। इसे मुख्यालय के स्तर पर हरी झंडी दे दी है और प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी इसकी कभी भी घोषणा कर सकते हैं। एनडीए के घटक दलों के बीच विधानसभा की 403 सीटों की शेयरिंग को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गयी है और इसके लिए जल्द ही बैठक होगी। एनडीए के घटक दलों में सीट शेयरिंग का फार्मूला भाजपा के लिए चुनौती बन सकता है। मोदी सरकार के बारह साल पूरे होने पर पिछले दिनों हुई एनडीए की बैठक में यूपी से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के संजय निषाद ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से इस बारे में चर्चा की थी। वहीं दूसरे दिन भाजपा मुख्यालय में भी राजभर ने नितिन नवीन से मुलाकात की। बाद में राजभर और संजय निषाद ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल से भी मुलाकात की।इन बैठकों में चुनाव और सीट शेयरिंग जैसे मुद्दों पर बात हुई। पार्टी ने सरकार के बारह साल पर पार्टी के जनसम्पर्क अभियान के रविवार को पूरा होने के बाद इस पर चर्चा शुरू करने के संकेत दिए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा उन पर सहयोगी दलों ने नजर जमाना शुरू कर दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी को 18 जिलों में हार का सामना करना पड़ा था। लोकसभा के परिणाम को भी ध्यान में रखते हुए अब पार्टी का सहारनपुर, मुरादाबाद, अयोध्या और आजमगढ़ मंडलों पर ज्यादा फोकस है। हाल ही संजय निषाद ने दिल्ली में सहारनपुर, मेरठ एवं आगरा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। वे पूर्वांचल तक सीमित नहीं रहना चाहते। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी(सुभासपा) ने पिछले दिनों 63 सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है।राष्ट्रीय लोक दल पश्चिमी यूपी में अपनी ताकत बढ़ाने पर जोर देता दिख सकता है।

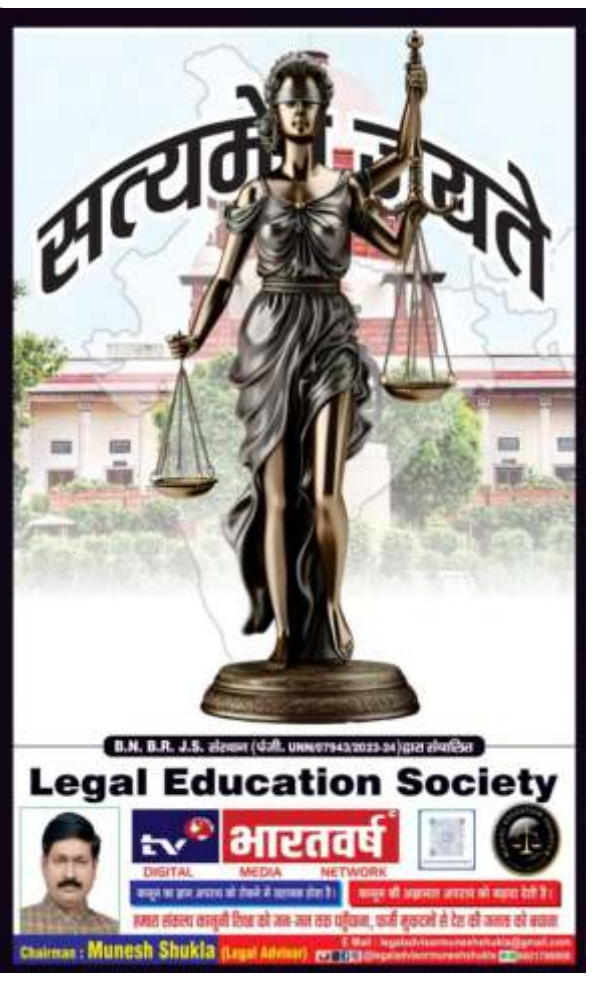

पीएचडी और शोध को बढ़ावा देने के लिए फेलोशिप

योजनाओं का विस्तार,हजारों शोधार्थियों को मिलेगा लाभ

देश में उच्च शिक्षा और शोध को नई गति देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार तथा विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों ने शोधार्थियों के लिए फेलोशिप और वित्तीय सहायता योजनाओं के विस्तार पर जोर दिया है। शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ी संस्थाओं द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हजारों पीएचडी शोधार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसका उद्देश्य प्रतिभाशाली छात्रों को शोध कार्य की ओर आकर्षित करना और भारत को ज्ञान एवं नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में मजबूत बनाना है।वर्तमान समय में जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ), सीनियर रिसर्च फेलोशिप (एसआरएफ), प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप (पीएमआरएफ) और विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों की विशेष योजनाओं के तहत शोधार्थियों को प्रतिमाह 37 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त अनुसंधान कार्यों के लिए अलग से अनुदान, प्रयोगशाला सुविधाएं और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शोध प्रस्तुत करने के अवसर भी दिए जा रहे हैं।शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में शोध संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण

कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को अधिक महत्व दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि भारतीय विश्वविद्यालय केवल डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान न रहकर वैश्विक स्तर के शोध केंद्रों के रूप में विकसित हों। इसी दिशा में उद्योग और विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।हालांकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि केवल फेलोशिप राशि बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। शोध के लिए बेहतर प्रयोगशालाएं, आधुनिक उपकरण, गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी उतना ही आवश्यक है। कई विश्वविद्यालयों में अब भी संसाधनों की कमी शोध की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। ऐसे में सरकार और शैक्षणिक संस्थानों को बुनियादी ढांचे के विकास पर भी समान रूप से ध्यान देना होगा।छात्र संगठनों ने फेलोशिप योजनाओं के विस्तार का स्वागत किया है, लेकिन समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि कई बार शोधार्थियों को महीनों तक भुगतान का इंतजार करना पड़ता है, जिससे आर्थिक कठिनाइयां पैदा होती हैं।विशेषज्ञों के अनुसार यदि शोध और नवाचार को इसी प्रकार प्रोत्साहन मिलता रहा तो आने वाले वर्षों में भारत विज्ञान, तकनीक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर और मजबूत स्थिति हासिल कर सकता है। इससे न केवल नई खोजों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी।

विश्वविद्यालयों में बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा, छात्रों को मिलेंगे नए अवसर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में देशभर के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में तेजी से काम किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पहल पर बहुविषयक शिक्षा, कौशल विकास और शोध आधारित अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य छात्रों को पारंपरिक शिक्षा के साथ-साथ रोजगारोन्मुख और व्यावहारिक ज्ञान उपलब्ध कराना है।नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को विषय चयन में अधिक स्वतंत्रता देने पर जोर दिया गया है। अब विद्यार्थी विज्ञान, वाणिज्य और कला जैसी पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़कर विभिन्न विषयों का संयोजन चुन सकते हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इससे छात्रों की रचनात्मकता और समस्या समाधान क्षमता में वृद्धि होगी तथा वे बदलती वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को तैयार कर सकेंगे।देश के कई विश्वविद्यालयों में चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम, बहु-प्रवेश और बहु-निकास व्यवस्था तथा अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जैसी व्यवस्थाओं को लागू किया जा चुका है। इन सुधारों का उद्देश्य छात्रों को अधिक लचीलापन प्रदान करना और उच्च शिक्षा को अधिक समावेशी बनाना है। साथ ही डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षण संसाधनों के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।हालांकि कुछ शिक्षाविदों का मानना है कि नई नीति के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए राज्यों, विश्वविद्यालयों और शिक्षकों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के संस्थानों में संसाधनों की उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।शिक्षा मंत्रालय का दावा है कि नई शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नीति का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है तो आने वाले वर्षों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, शोध क्षमता और रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल सकता है।

क्या अब हरमनप्रीत दोहराएंगी इतिहास?

डेरिल कलिनन ने वैभव सूर्यवंशी के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की

दुनिया भर के दिग्गज क्रिकेटर की जुबां पर आज कल सिर्फ एक ही नाम है और वह हैं भारतीय युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। 15 साल के इस खिलाड़ी ने हाल ही श्रीलंका ए के खिलाफ ट्राई नेशन ए सीरीज के फाइनल में सिर्फ 11 गेंदों पर अर्धशतक जड़ एक बार सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सूर्यवंशी का गेम पूरी तरह से पावर हिटिंग पर आधारित है। इसके लिए उन्हें हर शॉट के लिए जबरदस्त बैट स्पीड की जरूरत होती है। हालांकि टाइमिंग और तकनीक भी उतनी ही जरूरी हैं, लेकिन वैभव के स्ट्रोक प्ले पर भरोसे ने साउथ अफ्रीका के महान खिलाड़ी डेरिल कलिनन चिंतित हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर की टेनिस एल्बो चोट का उदाहरण देते हुए चेताया है। कलिनन ने सूर्यवंशी की मैच जिताने वाली 94 रन की पारी के बाद लिंक्डइन पर पोस्ट में कहा कि मैं इस युवा खिलाड़ी के प्रदर्शन से बहुत खुश हूं। लेकिन, मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। 15 साल की उम्र में उसका बड़ा बल्ला घुमाना, इतना क्रिकेट खेलना, मुझे उसकी कलाइयों, कोहनी, छोटी-मोटी चीजों और जोड़ों की चिंता है। मेडिकल राय क्या कहती है? उन्होंने बताया कि एक सचिन तेंदुलकर का करियर कोहनी की चोट की वजह से लगभग खत्म हो गया था। वह निश्चित रूप से सूर्यवंशी जितनी जोरदार स्विंग नहीं कर पाते थे। उन्होंने एक कमेंट का जवाब में लिखा कि मुझे

लगता है कि उनका रूटीन काफी सख्त होगा। बात यह है कि वह अभी बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि उनके जोड़, लिगामेंट और मसल्स भी बढ़ रहे होंगे। उन पर जोर पड़ेगा। मैं आपको यकीन दिला सकता हूं। उन्होंने आगे कहा कि मैं कुछ ऐसे खिलाड़ियों को जानता हूं, जिन्हें कलाई की पुरानी समस्याएं थीं। बात यह है कि हम हल्के बल्ले इस्तेमाल कर रहे थे, बहुत कम क्रिकेट खेल रहे थे। जबकि वह अभी भी बढ़ रहा है, जिसे याद रखने की जरूरत है। आज की ट्रेनिंग और रिकवरी के तरीके उसकी मदद करेंगे, लेकिन मुझे उसके लंबे समय के भविष्य और सेहत की चिंता है।

सिर्फ एक फॉर्मेट खेलने के बावजूद टीम में जगह पक्की नहीं- महेदी हसन

बांग्लादेश क्रिकेट टीम के टी20 स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर महेदी हसन ने टीम में लगातार मौके न मिलने पर निराशा व्यक्त की है। उनका मानना है कि बार-बार टीम से अंदर-बाहर होने के कारण वह इंटरनेशनल लेवल पर अपना बेस्ट प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खत्म हुई टी20 सीरीज के पहले मैच में महेदी हसन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उन्होंने नंबर 8 पर बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 29 रन बनाए और गेंदबाजी में 29 रन देकर 1 विकेट भी चटकाया। इसके बावजूद, उन्हें अगले दोनों मैचों की प्लेइंग XI से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।माना जा रहा है कि पहले मैच के पावरप्ले में विकेट न निकाल पाने के कारण टीम मैनेजमेंट ने उनकी जगह बाएं हाथ के स्पिनर नासुम अहमद को टीम में शामिल किया था। महेदी हसन ने टी-स्पोर्ट्स (T-Sports) से बातचीत में अपना दुख साझा करते हुए कहा कि एक क्रिकेटर के तौर पर मलाल तो रहता ही है। मैं सिर्फ टी20 फॉर्मेट खेलता हूं, लेकिन इसके बावजूद टीम में मेरी जगह पक्की नहीं है। अक्सर मुझे मैचअप या टीम कॉम्बिनेशन के नाम पर बाहर बैठना पड़ता है, जो बेहद निराशाजनक है। अगर मुझे लगातार खेलने का मौका मिले, तो मैं पहले से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर सकता हूं। महेदी का मानना है कि केवल एक ही फॉर्मेट खेलने वाले क्रिकेटर के लिए टीम में अपनी जगह बचाए रखना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, वे लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट के संपर्क में रहते हैं। लेकिन उन्हें सिर्फ टी20 खेलने के कारण मैचों के बीच में एक-दो महीने तक का इंतजार करना पड़ता है। कई बार तो दो या तीन मैचों की छोटी सीरीज में भी उन्हें सभी मैच खेलने को नहीं मिलते।

सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं मेसी

FIFA वर्ल्ड कप 2026 में अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी सोमवार को ऑस्ट्रिया के खिलाफ होने वाले ग्रुप-J के मैच में फुटबॉल इतिहास के कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब हैं। इससे पहले, अल्जीरिया के खिलाफ खेले गए मैच में अर्जेंटीना ने 3-0 से शानदार जीत दर्ज की थी। उस मैच में मेसी ने अपने करियर की पहली वर्ल्ड कप हैट्रिक लगाई थी और अर्जेंटीना के लिए अपना 200वां मैच भी पूरा किया था। अब 38 साल के मेसी की नजरें ऑस्ट्रिया के खिलाफ होने वाले मुकाबले में तीन नए रिकॉर्ड्स अपने नाम करने पर हैं। आइए जानते हैं वे कौन-से रिकॉर्ड्स हैं।लियोनेल मेसी पिछले लगातार 5 वर्ल्ड कप मैचों में गोल कर चुके हैं। अगर वह ऑस्ट्रिया के खिलाफ भी कम से कम एक गोल कर देते हैं, तो वह लगातार 6 वर्ल्ड कप मैचों में गोल करने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। फिलहाल यह रिकॉर्ड संयुक्त रूप से फ्रांस के जस्ट फोंटेन और ब्राजील के जाइरजिन्हो के

नाम है। मेसी के पास इस मैच में इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी करने का मौका होगा। ऑस्ट्रिया के खिलाफ सिर्फ एक गोल करते ही मेसी फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। इस समय वह 16 गोल के साथ जर्मनी के महान खिलाड़ी मिरोस्लाव क्लोस की बराबरी पर हैं। इसके साथ ही अगर मेसी यह गोल पेनल्टी बॉक्स के बाहर (लॉन्ग-रेंज) से करते हैं, तो वह वर्ल्ड कप इतिहास में बॉक्स के बाहर से सबसे ज्यादा गोल करने का नया रिकॉर्ड भी बना देंगे। मेसी अब तक बॉक्स के बाहर से 5 गोल दाग चुके हैं। अगर ऑस्ट्रिया के खिलाफ इस मैच में अर्जेंटीना जीत दर्ज करने में कामयाब होती है, तो वर्ल्ड कप में यह मेसी की 17वीं जीत होगी। इसके साथ ही वह वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा मैच जीतने के मिरोस्लाव क्लोस के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। मेसी अब तक 16 वर्ल्ड कप मैच जीत चुके हैं। मिरोस्लाव क्लोस वर्ल्ड कप में 17 मैच जीतने में कामयाब रहे थे।

करिश्मा कपूर ने पूरे किए बॉलीवुड़ में 35 साल, 'प्रेम कैदी' को किया याद

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने 35 साल पूरे होने पर भावुक पोस्ट साझा की है। करिश्मा ने बताया कि उनकी पहली फिल्म 'प्रेम कैदी' उनके 17वें जन्मदिन से ठीक चार दिन पहले रिलीज हुई थी।

अभिनेत्री ने कहा कि 16 वर्ष की उम्र में स्कूल छात्रा से फिल्म स्टार बनने का सफर उनके लिए अविस्मरणीय रहा। करिश्मा ने अपने तीन दशक से अधिक लंबे करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और हिंदी सिनेमा की सफल अभिनेत्रियों में अपनी पहचान बनाई।

उन्होंने कहा कि दर्शकों का प्यार ही उनके लंबे सफर की सबसे बड़ी पूंजी रहा है।

- पहली फिल्म 'प्रेम कैदी' 17वें जन्मदिन से चार दिन पहले हुई थी रिलीज
- 35 साल के करियर में कई सुपरहिट फिल्में
- दर्शकों के प्यार को बताया सबसे बड़ी पूंजी

भारत और अमेरिका के वर्क कल्चर में क्या है फर्क?

सोशल मीडिया पर अक्सर अमेरिका की वर्क लाइफ और वहां की संस्कृति को लेकर पोस्ट वायरल होती रहती हैं. ऐसी ही एक पोस्ट इन दिनों चर्चा में है. अमेरिका में रह रहे भारतीय युवक रवि आर. कुमार ने एक पोस्ट साझा करते हुए वहां के कामकाज के तरीके के बारे में बताया. उन्होंने लिखा कि अमेरिका में कई दफ्तर सुबह 8:30 बजे ही काम शुरू कर देते हैं. ऐसे में दोपहर 3 बजे तक लोगों का दिन का बड़ा हिस्सा पूरा हो जाता है. ⊙

शादी की शर्त ने मचाया बवाल

अपर कास्ट या फिर 80 लाख की कमाई जरूरी

क्या आज भी शादी में प्यार से ज्यादा जाति और पैसा मायने रखते हैं? हाल ही में सामने आई एक घटना ने इसी सवाल को फिर से चर्चा में ला दिया है. एक पढ़ी-लिखी और सफल महिला ने अपनी शादी के लिए ऐसी शर्त रख दी, जिसने आधुनिक सोच पर सवाल खड़े कर दिए- या तो दूल्हा 'उच्च जाति' का हो, वरना उसकी कमाई 80 लाख रुपये सालाना होनी चाहिए. इस एक शर्त ने दिखा दिया कि आज भी समाज में जाति और स्टेटस की सोच कितनी गहराई से जुड़ी हुई है, भले ही हम खुद को कितना भी प्रगतिशील क्यों न मान लें.

कहानी एक 32 साल की महिला की है, जो अपना खुद का फैशन बिजनेस चलाती है. वह एक अच्छे और पढ़े-लिखे परिवार से आती है. उसके पिता आईपीएस अधिकारी हैं और मां एक टीचर हैं. यानी बाहर से देखने पर वह एक आधुनिक और प्रगतिशील सोच वाले परिवार की लगती है. लेकिन जब बात शादी की आई, तो उसने दूल्हे के लिए एक खास शर्त रखी. ⊙

अमाल मलिक का बड़ा खुलासा, बोले- 'मुझे 60 फिल्मों से हटाया गया'

मुंबई। बॉलीवुड के लोकप्रिय संगीतकार अमाल मलिक ने फिल्म इंडस्ट्री को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि उन्हें अब तक करीब 60 फिल्मों से बाहर कर दिया गया। अमाल ने कहा कि आने वाली फिल्म 'आवारापन 2' उनके लिए केवल एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि खुद को साबित करने का अवसर है।

उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में सफलता और असफलता के आधार पर लोगों का व्यवहार बदल जाता है। अमाल ने बताया कि 'आवारापन 2' से जुड़ने की घोषणा के बाद उन्हें कई लोगों के फोन आए, लेकिन अब वह केवल अच्छे संगीत पर ध्यान देना चाहते हैं।

संगीतकार के इस बयान के बाद बॉलीवुड में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।

- करीब 60 फिल्मों से बाहर किए जाने का दावा
- 'आवारापन 2' से करेंगे दमदार वापसी
- अब केवल अच्छा संगीत देने पर रहेगा ध्यान

'वेलकम टू द जंगल' को सेंसर बोर्ड की हरी झंडी, रिलीज से पहले 18 बदलाव अनिवार्य

मुंबई। अक्षय कुमार की बहुप्रतीक्षित मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफटि) ने रिलीज से पहले 18 बदलावों के बाद मंजूरी दे दी है। फिल्म को यू/ए 16+ प्रमाणपत्र दिया गया है।

सेंसर बोर्ड ने कुछ संवादों, दृश्यों और संदर्भों में बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म में दिशा पाटनी और जैकलीन फर्नांडिस से जुड़े कुछ दृश्यों में भी संशोधन किया गया है।

अहमद खान के निर्देशन में बनी यह फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्री, परेश रावल, अरशद वारसी, जॉनी लीवर और कई अन्य कलाकार प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे।

दल-बदल की अफवाहों पर सपा का पलटवार, आरके चौधरी के समर्थन में थाने पहुंचे नेता

मोहनलालगंज सांसद आरके चौधरी के दल-बदल की अफवाहों पर सपा नेताओं ने कड़ा विरोध जताया। मुख्य सलाहकार टीबी सिंह ने काकोरी थाने में शिकायत दर्ज कराई। सपा ने अफवाहों को दुष्प्रचार बताते हुए पार्टी की एकजुटता का दावा किया।

लखनऊ। मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद आरके चौधरी के कथित दल-बदल को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे वीडियो और पोस्ट के माध्यम से सांसद के पार्टी छोड़ने की अफवाहें फैलाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसे सुनियोजित दुष्प्रचार करार दिया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए सांसद के मुख्य सलाहकार एवं समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष टीबी सिंह ने काकोरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। टीबी सिंह ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया कि कुछ असामाजिक और राजनीतिक तत्व जानबूझकर भ्रामक वीडियो और पोस्ट प्रसारित कर समाजवादी पार्टी तथा सांसद आरके चौधरी की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को भ्रमित करने और राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से झूठी सूचनाएं फैलाई जा रही हैं, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह एकजुट है और पार्टी के सभी 37 सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में मजबूती से खड़े हैं। सांसद आरके चौधरी के दल-बदल की खबरों में कोई सत्यता नहीं है। यह केवल विपक्षी तत्वों द्वारा फैलाया गया दुष्प्रचार है, जिसका उद्देश्य पार्टी की एकता और जनाधार को नुकसान पहुंचाना है। मामले को लेकर सांसद प्रतिनिधि तरुण रावत ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए राजनीतिक विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि "कुछ छुटभैये नेता बिच्छू का मंत्र नहीं जानते और सांप के बिल में हाथ डाल रहे हैं।" उन्होंने कहा कि विपक्ष को समाजवादी पार्टी पर अनर्गल टिप्पणी करने के बजाय अपने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। रावत ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी प्रदेश में लगातार मजबूत हो रही है और जनता का समर्थन पार्टी के साथ बना हुआ है। शिकायत दर्ज कराने के दौरान समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी काकोरी थाने पहुंचे। इनमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सरनाम सिंह यादव, प्रदेश सचिव रूप नारायण यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष सीएल वर्मा, पूर्व विधायक अम्ब्रीश सिंह पुष्कर, पूर्व प्रत्याशी राजबाला रावत, विजयश्री गौतम, पन्ना लाल रावत, जीत बहादुर रावत, इशाक गाजी, सत्येंद्र रावत, उमाशंकर वर्मा, अंजनि प्रकाश, मनोज सिंह, रज्जनलाल यादव, मुईन खां, मोहम्मद इब्राहिम मंसूरी, वीरेन्द्र सिंह यादव, मनीष यादव, राजेश सविता, अनुपम यादव और लालू यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और वायरल वीडियो तथा पोस्ट की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने चेतावनी दी है कि पार्टी और उसके जनप्रतिनिधियों की छवि खराब करने की किसी भी कोशिश का कानूनी और राजनीतिक स्तर पर जवाब दिया जाएगा।

सिविल अस्पताल में युवक का हंगामा

हजरतगंज स्थित सिविल अस्पताल में रविवार रात को एक युवक ने जमकर हंगामा किया। युवक ने अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की, जिससे वह खुद भी घायल हो गया। हाथ में शीशे का टुकड़ा लेकर उसने अपना गला काटने की धमकी दी और आसपास मौजूद लोगों की ओर भी शीशा तानने दौड़ पड़ा। हंगामे के दौरान युवक ने डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के साथ अभद्रता की। अचानक हुए घटनाक्रम से अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची हजरतगंज पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद युवक को काबू में लिया और उसे अपने साथ थाने ले गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, युवक नशे की हालत में था और लगातार उत्पात मचा रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया- युवक की पहचान चौक निवासी मुस्ताक के रूप में हुई है। युवक की मानसिक हालत ठीक नहीं है। चोट लगने पर खुद इलाज के पहुंचा था तभी किसी बात पर वार्ड से कहासुनी हो गई। इसके बाद हंगामा कर दिया।

एफडी के नाम पर लाखों डूबे, बैंक में ग्राहकों का हंगामा

शकुंतला विश्वविद्यालय परिसर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में एक बार फिर सोमवार को ग्राहकों ने प्रदर्शन कर दिया। 25 से ज्यादा खाताधारकों ने शाखा पहुंचकर कामकाज ठप करा दिया। अंदर घुसकर नारेबाजी की। कई ग्राहक फर्श पर बैठे तो कई लेट गए। उनका आरोप है कि FD के नाम पर बैंक मित्र ने उनसे लाखों रुपए लिए लेकिन FD नहीं की। खाताधारकों का आरोप है कि बैंक मित्र शिवा राव और उसके साथी दीपक ने अधिक ब्याज का लालच देकर उनसे एफडी के नाम पर लाखों रुपए जमा कराए थे। बाद में उन्हें पता चला कि उनके नाम पर कोई वैध एफडी नहीं की गई थी। 22 मई को बैंक के हेड ऑफिस में प्रदर्शन के बाद 22 जून को पैसा वापस आने का आश्वासन मिला था, जो नहीं हुआ। पीड़ितों ने बताया कि 22 मई को बैंक के हेड ऑफिस में अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्हें 22 जून तक पैसा वापस करने का आश्वासन दिया गया था। तय समय सीमा पूरी होने के बावजूद भुगतान नहीं होने से गुस्साए

खाताधारक सोमवार दोपहर करीब 12 बजे बैंक पहुंचे और प्रदर्शन शुरू कर दिया। खाताधारकों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी जमा पूंजी वापस नहीं मिलेगी, तब तक बैंक का कोई भी कार्य नहीं होने दिया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान बैंक का मुख्य गेट बंद कर दिया गया और सभी लोग अपनी मांगों को लेकर बैंक के अंदर ही डटे रहे। प्रदर्शन में रुचि गौतम (6 लाख रुपए), सुषमा (2 लाख), सरोजिनी (10 लाख), टिंकू (2 लाख), गुड़िया (1.60 लाख), मोनी राजपूत (1 लाख), फूलचंद (5 लाख), जयश्री (7 लाख), रामादेवी (1.80 लाख) और अनीता वर्मा (2 लाख) सहित कई अन्य पीड़ित शामिल थे। उन्होंने अपनी जीवनभर की बचत फंसने और आर्थिक संकट से जूझने की बात कही।

सड़क हादसे में युवक की मौत, परिजनों का प्रदर्शन

काकोरी क्षेत्र के गोला कुआं गांव के पास सड़क हादसे में युवक हिमालय गौतम की मौत के बाद रविवार को परिजनों और किसान नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान हाईवे जाम करने का प्रयास किया गया, जिससे कुछ देर यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल 158 लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इनमें 8 लोग नामजद हैं और शेष 150 लोगों की पुलिस वीडियो के आधार पर कर रही है। शनिवार रात हुए हादसे में हिमालय गौतम की जान चली गई थी। पोस्टमॉर्टम के बाद उनका शव गांव पहुंचने की सूचना मिलते ही भारतीय किसान यूनियन (हिंदुस्तान) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद सलमान अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे। किसान नेताओं और परिजनों ने आरोपी थार चालक की तत्काल गिरफ्तारी, मृतक के परिजनों को एक करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। सूचना मिलने पर मलिहाबाद के एसडीएम अंकित मौर्य घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने किसान नेताओं और परिजनों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया। किसान नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। एसडीएम ने नियमानुसार हरसंभव सहायता और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

UPSSSC के मुख्यालय पहुंचे जूनियर असिस्टेंट अभ्यर्थी

लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) के मुख्यालय के बाहर सोमवार को जूनियर असिस्टेंट अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हुए तीन साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। इससे युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। हरदोई से आए एक अभ्यर्थी ने कहा कि फार्म भरने के बाद से ही लगातार आंदोलन करना पड़ रहा है। कभी वैकेंसी को लेकर, तो कभी परीक्षा कराने की मांग को लेकर और अब रिजल्ट जारी कराने के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने बताया कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। अलग-अलग जिलों से अभ्यर्थी समय-समय पर लखनऊ पहुंचकर प्रदर्शन करते हैं और आयोग व संबंधित अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी बात रखते हैं। हालांकि हर बार उन्हें आश्वासन तो मिलता है, लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है और नियुक्तियां भी नहीं हुई हैं।

लखनऊ नगर निगम कार्यकारिणी में 6 सदस्य निर्विरोध चुने गए

लखनऊ नगर निगम की कार्यकारिणी समिति में सोमवार को 6 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो गए। इसमें 5 पार्षद भाजपा के चुने गए हैं और सपा की एक पार्षद शामिल है। सपा के वरिष्ठ पार्षद यायावर हुसैन रेशू को तय माना जा रहा था लेकिन सुबह नाम ममता रावत का भेज दिया गया। 2 वर्षीय कार्यकाल वाली इस कार्यसमिति के 6 सदस्यों का इसी महीने कार्यकाल समाप्त हुआ था। कार्यकारिणी समिति के चुनाव के लिए लालबाग स्थित नगर निगम मुख्यालय के त्रिलोकनाथ सभागार में सुबह 11 बजे विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। भाजपा ने 5 पार्षदों के नाम घोषित किए थे। दूसरी पार्टियों ने एक भी नाम नहीं भेजे थे। समाजवादी पार्टी ने 1 नाम देने के लिए रातभर मंथन किया। लगभग तय था कि यायावर हुसैन रेशू का नाम भेजा जाएगा। लेकिन, चुनाव से कुछ घंटे पहले विपक्षी दल के नेता कामरान बेग ने ममता का नाम दे दिया। पुराने सदस्य जिनका अभी कार्यकाल चल रहा है, उनमें भाजपा के अरुण राय, पृथ्वी गुप्ता, पिंकी रावत, राजेश सिंह गब्बर, संदीप शर्मा और सपा के रामनरेश चौरसिया शामिल हैं। इस साल 1 जून को 6 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया था। उनमें भाजपा के भृगुनाथ शुक्ला, अनुराग मिश्रा, गौरी सांवरिया, कृष्ण नरायन सिंह, चरनजीत गांधी और सपा की सबा हसन मंसूरी शामिल थीं। चरनजीत सिंह गांधी

अभी तक नगर निगम की उपाध्यक्ष थीं। उनको पिछले साल उपाध्यक्ष चुना गया था। उनका कार्यकारिणी से कार्यकाल खत्म होने के बाद भाजपा के सुशील तिवारी पम्मी को उपाध्यक्ष के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा है। हालांकि, जानकारों का मानना है कि सपा ने कार्यकारिणी को महिला कैंडिडेट देकर महिला उपाध्यक्ष को लेकर संदेश दिया है। सपा की ओर से पहले जगदीश चंद्र बोस वार्ड से लगातार 6 बार जीत दर्ज करने वाले पार्षद यायावर हुसैन रेशू को प्रत्याशी बनाए जाने की संभावना देर रात तक थी, लेकिन सुबह सदन में अचानक पहली बार भरवारा मल्हौर वार्ड से पार्षद बनी ममता रावत को टिकट दे दिया गया। टिकट देने की जानकारी महापौर को ममता रावत ने दल के नेता कामरान बेग से फोन पर बात कराकर दी। चुनाव के दौरान सपा पार्षद दल के नेता कामरान बेग सदन में मौजूद नहीं रहे।

एआरटीओ का पलटवार: डेटा एंट्री ऑपरेटर के आरोप निराधार,

नियम विरुद्ध कार्यों पर हुई कार्रवाई

एआरटीओ कार्यालय में कार्यरत डेटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर विभाग और कर्मचारी के बीच विवाद गहराता नजर आ रहा है। इस मामले में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) श्वेता वर्मा ने सामने आकर कर्मचारी द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी शिव सिंह के खिलाफ विभागीय नियमों के उल्लंघन और कार्य में गंभीर अनियमितताओं के कारण कार्रवाई की गई थी, जिसे अब वह गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। एआरटीओ श्वेता वर्मा ने बताया कि डेटा एंट्री ऑपरेटर शिव सिंह द्वारा कई मामलों में स्क्रूटनी के दौरान गंभीर त्रुटियां की जा रही थीं। जांच के दौरान यह पाया गया कि कुछ प्रकरणों में निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया। इस संबंध में संबंधित आउटसोर्सिंग कंपनी को पत्र लिखकर कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा उसके स्थान पर दूसरे कर्मचारी की तैनाती की मांग की गई थी। इस पत्र की प्रतिलिपि विभाग के उच्च अधिकारियों को भी भेजी गई थी।उन्होंने कहा कि विभागीय कार्रवाई से नाराज होकर कर्मचारी अब कार्यालय और अधिकारियों की छवि खराब करने का प्रयास कर रहा है। मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह बेबुनियाद और तथ्यों से परे हैं। उनका उद्देश्य केवल विभाग पर दबाव बनाना और कार्रवाई को प्रभावित करना है। मेडिकल प्रमाण पत्रों में कथित फर्जीवाड़े के आरोपों पर भी एआरटीओ ने स्पष्ट जवाब दिया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में परिवहन विभाग की अधिकांश प्रक्रियाएं ऑनलाइन संचालित होती हैं। मेडिकल प्रमाण पत्र भी पूरी तरह डिजिटल प्रणाली के माध्यम से जारी किए जाते हैं। संबंधित चिकित्सक अपनी अधिकृत आईडी से मेडिकल परीक्षण के बाद प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करते हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की हेराफेरी या फर्जीवाड़े की संभावना नहीं रहती।ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों को लेकर उठाए गए सवालों पर श्वेता वर्मा ने बताया कि जिले में वर्तमान समय में पांच मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल संचालित हैं। इन संस्थानों की नियमित रूप से जांच की जाती है। संभागीय निरीक्षक (आरआई) और विभागीय अधिकारी समय-समय पर इनकी कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हैं। व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस इन्हीं संस्थानों द्वारा जारी प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों के आधार पर बनाए जाते हैं।उन्होंने कहा कि अब तक किसी भी ट्रेनिंग स्कूल के खिलाफ फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने अथवा नियमों के उल्लंघन की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यदि भविष्य में ऐसी कोई शिकायत सामने आती है तो नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एआरटीओ ने यह भी बताया कि कर्मचारी शिव सिंह पूर्व में लखनऊ में तैनात थे, जहां उनके कार्य व्यवहार और कार्यप्रणाली को लेकर शिकायतें सामने आई थीं। इन्हीं शिकायतों के आधार पर उन्हें वहां से हटाया गया था। उन्नाव में तैनाती के बाद भी उन्हें कई बार कार्यशैली में सुधार के लिए मौखिक और लिखित रूप से चेतावनी दी गई, लेकिन अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।उन्होंने कहा कि विभाग ने पहले सुधार का अवसर दिया, लेकिन जब स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया तो नियमों के तहत सख्त कदम उठाना पड़ा। विभाग द्वारा की गई कार्रवाई पूरी तरह नियमसम्मत और प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों पर कार्य करता है तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

शराब पार्टी में चली गोली, युवक गंभीर रूप से घायल

उन्नाव के गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र में पोनी रोड पर रविवार देर रात एक शराब पार्टी के दौरान देसी तमंचे से गोली चलने से एक युवक घायल हो गया। गोली युवक की कमर में लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए कानपुर के उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, शुक्लागंज के पोनी रोड निवासी 35 वर्षीय अजय कुमार अपने दोस्त विजय कश्यप और कुछ अन्य साथियों के साथ शराब पार्टी कर रहा था। इसी दौरान अचानक देसी तमंचे से गोली चल गई, जो सामने बैठे अजय की कमर में जा लगी। गोली लगने से अजय गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। घटना से घबराए उसके दोस्त तत्काल घायल अजय को लेकर कानपुर के उर्सला अस्पताल पहुंचे। अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और साथ आए युवकों से पूछताछ की। फीलखाना इंस्पेक्टर अभय कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में विजय कश्यप ने स्वीकार किया कि शराब पार्टी के दौरान अचानक तमंचे से गोली चल गई थी, जो अजय को लग गई। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

उन्नाव में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज

उन्नाव में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को भव्य और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए दूसरी बैठक आयोजित की गई। इसमें समिति के पदाधिकारियों, वरिष्ठ सदस्यों और युवाओं ने भाग लिया। बैठक में यात्रा की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। यह बैठक राजधानी मार्ग स्थित मां बालेश्वरी स्मृति भवन, गिरधर ज्वेलर्स, नेहरू नगर में हुई। समिति के सदस्यों ने अपने सुझाव दिए, जिन पर चर्चा की गई। इन सुझावों को यात्रा की व्यवस्थाओं में शामिल करने की योजना बनाई गई, ताकि रथ यात्रा शांतिपूर्ण और भव्य हो सके। बैठक में रथ यात्रा में शामिल होने वाली झांकियों, ढोल-नगाड़ों और अन्य आकर्षणों पर भी बात हुई। समिति ने बताया कि शिव-पार्वती, राधा-कृष्ण, मां काली, हनुमान जी, गणेश जी, शिव सेना और भूत-प्रेत की झांकियां श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण होंगी। ये झांकियां और धार्मिक प्रस्तुतियां यात्रा की शोभा बढ़ाएंगी। नगर में दो रथ यात्राएं निकाले जाने की चर्चाओं पर समिति अध्यक्ष वीरेंद्र शुक्ला ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि गोपीनाथपुरम स्थित खाटू श्याम मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिमा स्थापित है। रथ का पूजन और यात्रा का शुभारंभ इसी स्थान से होगा। यात्रा का मार्ग पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही रहेगा। रथ यात्रा गोपीनाथपुरम से शुरू होकर नेहरू नगर, राजधानी मार्ग होते हुए अंबिका प्रसाद स्कूल मोड़ से आगे बढ़ेगी। इसके बाद यह राज गोल्डी गुप्ता के कार्यालय के पास से होते हुए कैलाश वाटिका के सामने कंचन नगर मोड़, गुड्डन टावर के सामने से दुर्गा मंदिर की ओर जाएगी और फिर कोई रोड की तरफ प्रस्थान करेगी। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि यात्रा मार्ग में कई स्थानों पर स्वागत कार्यक्रम होते हैं, जिससे भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी युवा मंडल को सौंपी गई है। युवाओं को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अप्रिय घटना न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

गंगापुल निर्माण की राह में मकान हटाने की कार्रवाई,

प्रभावितों ने मांगा पुनर्वास

शुक्लागंज में प्रस्तावित नवीन गंगापुल निर्माण परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन ने प्रभावित मकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को नायब तहसीलदार धीरज त्रिपाठी, जेई कुंदन, लेखपाल प्रशांत अवस्थी समेत अन्य अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन मशीन में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी और टीम को वापस लौटना पड़ा। मंगलवार को दोबारा बड़ी मशीन के साथ प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। सुबह करीब 10 बजे शुरू हुई कार्रवाई के दौरान दोपहर 12 बजे तक केवल एक मकान पर ही काम किया जा सका। अधिकारियों ने वेद प्रकाश चतुर्वेदी के मकान के लगभग 30 प्रतिशत हिस्से को ध्वस्त किया, जिसके बाद मशीन वापस लौट गई। इससे प्रभावित परिवारों में असमंजस की स्थिति बनी रही। पुल निर्माण से प्रभावित स्थानीय लोगों ने प्रशासन के समक्ष पुनर्वास और वैकल्पिक आवास की मांग उठाई। उनका कहना है कि पूर्व में उपजिलाधिकारी (एसडीएम) द्वारा पुनर्वास का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। प्रभावित परिवारों का कहना है कि मकान तोड़े जाने से पहले उनके रहने और पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।स्थानीय लोगों के अनुसार, नवीन गंगापुल परियोजना के लिए कुल 38 मकान प्रभावित हो रहे हैं, जिन्हें हटाया जाना प्रस्तावित है। ऐसे में बड़ी संख्या में परिवारों के सामने आवास का संकट खड़ा हो सकता है। प्रभावितों ने प्रशासन से मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उचित मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था करने की मांग की है। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनीं और उन्हें नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी किए गए थे।गौरतलब है कि नवीन गंगापुल परियोजना को क्षेत्र के विकास और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, परियोजना के साथ-साथ प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और मुआवजे का मुद्दा भी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है।

सफीपुर में पशुबाड़े में आग, सात भैंसें झुलसीं

उन्नाव के सफीपुर में एक पशुबाड़े में आग लगने से दो भाइयों की सात भैंसें गंभीर रूप से झुलस गईं। इस घटना में पशुबाड़े का छप्पर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने पर उपजिलाधिकारी (एसडीएम) और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। यह घटना सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के कस्बा सफीपुर के मोहल्ला गढ़ा-क़िलाबाजार में सोमवार दोपहर करीब 12 बजे हुई। वीरेंद्र और रामेंद्र पुत्रगण मथुरा प्रसाद के पशुबाड़े में अचानक आग लग गई। वीरेंद्र ने सुबह ही सभी पशुओं को छप्पर के नीचे बांधा था। आग की लपटें देखकर परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने तुरंत निजी संसाधनों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। उन्होंने 20 पशुओं में से सात भैंसों को झुलसी हुई हालत में बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पीड़ित रामेंद्र ने बताया कि उन्होंने पशु चिकित्सा के लिए डायल 1962 पर कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। एसडीएम शिवेंद्र वर्मा और लेखपाल विवेक सिंह ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। कोतवाल संदीप मिश्रा ने पशु चिकित्साधिकारी को सूचित किया, जिसके बाद पशुओं का उपचार शुरू हो सका। वीरेंद्र के अनुसार, छप्पर के ऊपर से गुजर रही घरेलू विद्युत केबल में जोड़ थे, जिससे शॉर्ट सर्किट होने की आशंका है। विद्युत निगम के कर्मचारियों ने भी मौके पर पहुंचकर संबंधित केबल हटा दिए हैं।

अखिलेश यादव के खिलाफ आपत्तिजनक बैनर लगाने का आरोप

उन्नाव के गदन खेड़ा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बैनर लगाए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर सपा नेताओं ने नाराजगी व्यक्त की है। सोमवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व सदर विधानसभा प्रत्याशी डॉ. अभिनव कुमार और पूर्व विधायक रामकुमार सदर कोतवाली पहुंचे। उन्होंने थाना प्रभारी को लिखित शिकायत देकर मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। डॉ. अभिनव कुमार ने अपने प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि गदन खेड़ा क्षेत्र में लगाए गए बैनरों के माध्यम से अखिलेश यादव के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन्होंने इसे निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सपा नेताओं ने पुलिस प्रशासन से क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर बैनर लगाने वालों की पहचान करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। थाना प्रभारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सपा नेताओं का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी राजनीतिक दल या नेता के खिलाफ ऐसी आपत्तिजनक गतिविधियां स्वीकार्य नहीं हैं। डॉ. अभिनव कुमार ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन द्वारा समय रहते दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो समाजवादी कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से धरना-प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। इस दौरान अंशु रावत और भरत सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में सीएम योगी की हाईलेवल बैठक,

विकास और कानून-व्यवस्था पर मंथन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विकास परियोजनाओं, कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को अपने निर्धारित दौरे के तहत राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिले और मंडल के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। विश्वविद्यालय परिसर में स्थित कुलपति कक्ष में आयोजित इस बैठक में विकास परियोजनाओं, कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आधारभूत ढांचे से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।मुख्यमंत्री के विश्वविद्यालय पहुंचते ही प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे सीधे कुलपति कक्ष पहुंचे और समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बैठक में जिले के सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी, मंडल स्तरीय अधिकारी तथा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा उनके क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री विशेष रूप से उन परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं जो लंबे समय से लंबित हैं या जिनका कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा नहीं हो पाया है। उन्होंने अधिकारियों से जमीनी स्तर पर हो रहे कार्यों की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली और विकास योजनाओं में तेजी लाने पर जोर दिया। साथ ही यह भी निर्देश दिए जाने की संभावना है कि जनता से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। बैठक के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति भी प्रमुख एजेंडे में शामिल रही। मुख्यमंत्री ने अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, पुलिस की कार्यप्रणाली और संवेदनशील क्षेत्रों की स्थिति को लेकर अधिकारियों से रिपोर्ट ली। उन्होंने जनसुनवाई, शिकायतों के निस्तारण और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं, अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं, चिकित्सकों की तैनाती और मरीजों को मिलने वाली सेवाओं की समीक्षा की गई। शिक्षा क्षेत्र में विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थिति, नई परियोजनाओं तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रयासों पर भी चर्चा हुई।बैठक में सड़क निर्माण, विद्युत आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था, नगरीय विकास और निवेश से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सभी विकास कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं और योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासनिक अमला पहले से ही अलर्ट मोड पर था। सुरक्षा व्यवस्था के भी व्यापक इंतजाम किए गए थे। समीक्षा बैठक को आगामी विकास योजनाओं और प्रशासनिक कार्यप्रणाली के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि बैठक के बाद मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों को विकास कार्यों में तेजी लाने और जनहित से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकते हैं। प्रदेश सरकार की प्राथमिकता जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। ऐसे में मुख्यमंत्री की यह समीक्षा बैठक जिले के विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्था को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है।

बिजनौर थाने में महिला रेसलर ने लगाई खुद को आग, हालत गंभीर

बिजनौर के कोतवाली शहर थाने में रविवार रात एक महिला रेसलर ने इंस्पेक्टर के चैंबर में पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा ली। घटना रात 10:45 बजे की है। आग लगते ही महिला रेसलर जान बचाने के लिए चिल्लाने लगी और इधर-उधर भागने लगी। इस दौरान चैंबर के पर्दों में भी आग लग गई, जिससे थाने में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत आग बुझाई और उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक इलाज किया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे मेरठ रेफर कर दिया। फिलहाल, महिला रेसलर की हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक, वह 60 प्रतिशत तक झुलस चुकी है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि महिला रेसलर का फौजी से प्रेम संबंध था। आरोप है कि फौजी ने शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में शादी से मुकर गया। इसके बाद महिला ने उसके खिलाफ रेप की FIR दर्ज कराई थी। हालांकि, आरोपी फौजी ने कोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे ले रखा है, जिस वजह से पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। इससे नाराज होकर उसने ऐसा कदम उठाया है। इस मामले में एसपी अभिषेक झा ने थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर अमर सिंह राठौर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है।

मेरठ में तेज रफ्तार कार ने 7 पुलिसकर्मियों को कुचला

मेरठ में ऑटो पार्ट्स कारोबारी के बेटे ने अपनी इनोवा कार से सड़क किनारे खड़े 7 पुलिसकर्मियों को रौंद दिया। इस दौरान एक कांस्टेबल का पैर टूट गया। दो के हाथों की खाल छिल गई। बाकी के मुंह और नाक में चोटें आईं हैं। मामले का CCTV सोमवार को सामने आया। इसमें दिख रहा है कि शनिवार देर रात ढाई बजे गश्त पर निकले पुलिसकर्मी रोड किनारे पुलिस लीप के पास खड़े थे। तभी तेज रफ्तार इनोवा कार ने पुलिसकर्मियों को रौंदते हुए जीप से टकरा गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को हिलने तक का समय नहीं मिला। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार की रफ्तार 100 से ज्यादा थी। टक्कर के बाद कांस्टेबल 5 फीट तक उछलकर दूर गिरे। मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इनमें से 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कारें जब्त कर लीं। ब्रह्मपुरी थानाक्षेत्र के सुपरटेक पामग्रीन, बिजली बंबा रोड निवासी कारोबारी रमन जोली के दो बेटे नमन जोली (37) और अमन जोली (35) हैं। दोनों भाई शनिवार देर रात दिल्ली हाईवे पर अपनी इनोवा और थार गाड़ी से रेस लगा रहे थे। दोनों एक-दूसरे को ओवरटेक करने की होड़ में थे। इसी दौरान इनोवा चला रहे बड़े भाई नमन जोली कार बेकाबू हो गई।

सीतापुर में सपा कार्यालय पर बुलडोजर कार्रवाई

यूपी के सीतापुर में सरकारी जमीन पर बने सपा कार्यालय को सोमवार तड़के बुलडोजर से ढहा दिया। जिला प्रशासन सुबह 4 बजे 5 थानों की फोर्स लेकर मौके पर पहुंचा। 4 बुलडोजरों ने 2 घंटे में कार्यालय को जमींदोज कर दिया। मलबा भी हटा दिया गया। इस दौरान 25 पुलिसकर्मी और 50 पीएसी जवान तैनात रहे। सपा कार्यालय 21 साल पहले 2500 स्क्वायर फीट जमीन पर बनाया गया था। सरकारी नजूल की जमीन पर सपा कार्यालय के नाम पट्टा दिया गया था। हालांकि, 4 महीने बाद ही पट्टा निरस्त कर दिया गया। उस वक्त मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। पट्टा निरस्त होने के बाद भी यहां सपा कार्यालय चलता रहा। 15 दिन पहले जिलाधिकारी कोर्ट ने सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल यादव को नोटिस भेजा था। उन्हें रविवार तक कार्यालय खाली करने का समय दिया गया था। बुलडोजर कार्रवाई से 24 घंटे पहले सपा जिलाध्यक्ष ने कार्यालय खाली करा दिया था। नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी (ईओ) सीमा सिंह ने बताया, '15 जनवरी, 2005 को तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष राधेश्याम जायसवाल ने टाउन हॉल परिसर की नजूल भूमि सपा के जिला कार्यालय के लिए आवंटित की थी। इसके लिए किराया सिर्फ 100 रुपए तय किया गया था।' उन्होंने बताया, '2500 स्क्वायर फीट जमीन पर एक हॉल और दो कमरे बनवाए गए थे।